International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

बिहार में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में जीविका परियोजना की भूमिका का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

अनुराग कुमार

शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार

सारांश:

बिहार राज्य में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहती है, 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में आधा जनसंख्या (47.86%) महिलाओं का है। इसलिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार महत्वपूर्ण हो जाता है। BRLPS (बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति), जिसे आमतौर पर 'जीविका' के रूप में जाना जाता है, बिहार सरकार की एक स्वायत्त संस्था है, जिसका स्थापना 2 अक्टूबर 2006 को बिहार सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और गरीबी को कम करना है। इस शोध पत्र के माध्यम से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार राज्य में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में परियोजना कैसे ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है। यह शोध डेटा के द्वितीय स्त्रोत पर आधारित है, जिसमें शोध पत्रिका, समाचार पत्र, एवं इंटरनेट से डेटा लिया गया है।

मुख्य शब्द: BRLPS (जीविका), SHGs, ग्रामीण महिला, समावेशन, बिहार

परिचय:

बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (BRLPS), जिसे आमतौर पर 'जीविका' के रूप में जाना जाता है, की स्थापना विश्व बैंक के सहयोग से 2006 में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया गया। यह बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण गरीबों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण हेतु शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के दिशानिर्देशों एवं वित्तीय सहायता के अंतर्गत बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति (BRLPS) द्वारा 'जीविका' परियोजना के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। साल 2005 में गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और पूर्णियां के चुनिंदा प्रखण्डों (बोधगया, हरनौत, बोचहां, राजनगर और धमदाहा) में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 'जीविका' शुरू किया गया। वर्ष 2007 में इसका विस्तार कर इसमें खगड़िया को भी जोड़ा गया और कुल छह जिलों से तीन प्रखंड को चुनते हुए 18 प्रखंडों में काम शुरू हुआ आज 'जीविका' कार्यक्रम सफलतापूर्वक राज्य के सभी 38 जिलों और सभी 534 प्रखंडों में अपनी पहुँच बना चुका है (कुमार और सिहं, 2025)।

जीविका कार्यक्रम के अंतर्गत समावेशी विकास का आशय एक ऐसी विकास प्रक्रिया से है जिसमें समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं और वंचित वर्गों को आर्थिक और सामाजिक प्रगति का हिस्सा बनाया जाए। ग्रामीण महिलाओं की प्रगति में शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव, सामाजिक रूढ़िवादी मानसिकता और निर्णय प्रक्रिया में नगण्य भागीदारी उनकी आत्मनिर्भरता में बड़ी बाधा रही है। इसी कारण ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर रती हैं (कुमार, 2026)।

जीविका का संरचना:

जीविका संरचना का मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है: सामुदायिक संस्था संरचना (ग्रासरूट स्तर) और प्रशासनिक संरचना (प्रबंधन)। प्रथम,

सामुदायिक संस्था संरचना (ग्रासरूट स्तर): प्राथमिक स्तर पर स्वयं सहायता समूह (SHG) जिसमे, 10-12 महिलाएँ होती है अपनी बचत के जरिए सामूहिक ऋण की शक्ति विकसित करती हैं। यह व्यवस्था निचले स्तर से ऊपर की ओर बढ़ती है, जिसमें SHG मिलकर ग्राम संगठन (VO) और फिर संकुल स्तरीय संघ (CLF) का ढांचा तैयार करते हैं। यह त्रिस्तरीय मॉडल न केवल सामाजिक एकजुटता बढ़ाता है, बल्कि शासन में महिलाओं की भागीदारी भी तय करता है (सिंह, 2025)। द्वितीय, प्रशासनिक संरचना (प्रबंधन): यह सरकारी नीति को जमीनी स्तर के स्वयं सहायता समूहों से जोड़ती है, जो तीन स्तरों पर संगठित हैं- राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू), जिला परियोजना समन्वय इकाई (डीपीसीयू) और ब्लॉक परियोजना कार्यान्वयन इकाई (बीपीआईयू)। इस प्रकार सामुदायिक संस्था संरचना (ग्रासरूट स्तर) और प्रशासनिक संरचना (प्रबंधन), पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग (जैसे जीविका परियोजना) के अंतर्गत कार्य करते हैं। ये महिलाओं को बैंकिंग, ऋण और खेती-बारी से जोड़कर उनकी आय बढ़ाता है, बल्कि उन्हें पंचायतों और सामुदायिक निर्णयों में नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। वर्तमान में जीविका, आर्थिक मजबूती को सामाजिक एकजुटता के साथ जोड़कर पारंपरिक सोच को बदल रही है और ग्रामीण महिलाओं को एक नई पहचान देते हुए बिहार में स्थायी सामाजिक परिवर्तन की नींव रख रही है (भारती, 2025)।

वित्तीय समावेशन:

जीविका के अंतर्गत वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य गाँव के गरीब परिवारों, खासकर महिलाओं को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। जिसके जरिए उन्हें आसान किश्तों और कम ब्याज पर लोन, बचत की सुविधा और बीमा जैसी सेवाएँ मुहैया कराई जाती हैं ताकि उनकी साहूकारों पर निर्भरता खत्म हो और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह (SHG), ग्राम संगठन (VO) तथा क्लस्टर स्तरीय महासंघ (CLF) की त्रिस्तरीय संरचना ने वित्तीय समावेशन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने मैं स्वयं सहायता समूह (SHG) का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, जिसका उपयोग वे कृषि, पशुपालन, लघु व्यवसाय और अन्य आयवर्धक गतिविधियों में करती हैं।

जीविका के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण आयाम बनकर उभरा है। जीविका ने महिलाओं को ऋण, बचत और आजीविका के अवसरों से जोड़कर उनकी आय और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है। महिलाओं ने सिलाई, पशुपालन, खेती और सूक्ष्म उद्यम जैसी गतिविधियों को अपनाकर अपने तथा अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। स्वयं सहायता समूहों और बैंकिंग सुविधाओं तक आसान पहुँच के कारण महिलाओं की साहूकारों पर निर्भरता कम हुई तथा घरेलू ऋणों में कमी आई। इसके अतिरिक्त, महिलाओं ने अपनी आय का उपयोग बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भूमि और परिसंपत्तियों की खरीद में किया, जिससे उनकी घरेलू निर्णय क्षमता और सामाजिक स्थिति मजबूत हुई (अमृत, 2020)।

सामाजिक समावेशन:

ग्रामीण बिहार में स्वयं सहायता समूहों (SHGs) ने महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं में आत्मविश्वास, स्वायत्तता, निर्णय लेने की क्षमता तथा सामाजिक पहचान का विकास करना है। जीविका कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं ने घरेलू और सामुदायिक स्तर पर अपनी भागीदारी बढ़ाई तथा पंचायत बैठकों, सामाजिक अभियानों और सामूहिक निर्णय प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं को एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क और सामूहिक पहचान प्रदान की, जिससे वे घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध संगठित होकर कार्य करने में सक्षम हुई। इसके अतिरिक्त सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (CRPs) के रूप में महिलाओं का नेतृत्व उभरकर सामने आया, जिसने ग्रामीण महिलाओं की नेतृत्व क्षमता और सामाजिक प्रभाव को बढ़ाया (अमृत, 2020)। सामाजिक चेतना का ही परिणाम है कि महिलाओं ने शिक्षा का महत्त्व समझा और वे अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए ऋण लेना शुरू किया ताकि वे आगे चल कर अपने आप समाज में स्थापित कर सके और अपनी कौशल के आधार पर स्वरोजगार अथवा सरकारी रोजगार कर सके। इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन और स्वच्छता के प्रति महिलाओं में जागरूकता पहले से बढ़ी है।

राजनीतिक चेतना का विकास:

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में जीविका का प्रभाव न सिर्फ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा बल्कि राजनीतिक क्षेत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के माध्यम से महिलाओं के बीच सहयोग और सामूहिकता की भावना विकास होता है, जिससे वे अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होतीं हैं। विशेष रूप से पिछड़ी एवं अत्यंत पिछड़ी जातियों की महिलाओं को इन समूहों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक पहचान प्राप्त हुई है (Kumar, 2023)। अब ग्रामीण महिलाएं परिवार के पुरुषों के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी पसंद से मतदान करती हैं। महिलाओं के नेतृत्व कौशल को निखारने में 'जीविका' ने सराहनीय योगदान है। सामाजिक जागरूकता और राजनीतिक चेतना का ही परिणाम है कि 'जीविका दीदियां' अपने नेतृत्व कौशल के आधार पर अब वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करती हैं।

ग्रामीण महिलाओं के लिए चुनौतियां:

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना बीआरएलपीएस जीविका ने महिला सशक्तिकरण में एक क्रांतिकारी परियोजना सिद्ध हुई है, परन्तु आज भी कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो इन ग्रामीण महिलाओं के प्रगति के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है जो इस प्रकार निम्नलिखित है। : -

1. 1.ग्रामीण महिलाओं के सामने अशिक्षा और जागरूकता की कमी एक बड़ी चुनौती है। इसका प्रभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण पर भी पड़ता है। इसबैंकिंग कार्यों, डिजिटल लेन-देन और व्यावसायिक हिसाब-किताब करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
2. लंबे समय तक सामाजिक दबाव और आत्मविश्वास में कमी के कारण कई महिलाएँ सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने में संकोच करती हैं।
3. कुमार (2023) ने पाया कि उच्च जाति या प्रभावशाली वर्ग के लोग समूहों और संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, जिससे निम्न जाति की महिलाओं को लाभ कम मिल पाता है।
4. महिलाओं को घर के काम, बच्चों की देखभाल और खेती/पशुपालन के साथ-साथ जीविका समूह की बैठकों और व्यवसाय को भी संभालना पड़ता है। इससे उन पर काम का अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है।

निष्कर्ष:

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बिहार में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में जीविका परियोजना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। जीविका परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक समावेशन के साथ-साथ राजनीतिक रूप से भी सशक्त किया है। जहाँ पहले ग्रामीण महिलाओं को आथिर्क रूप से पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था तथा निर्णय प्रक्रिया में नगण्य भूमिका रहती थी वहिं आज जीविका के माध्यम से ग्रामीण महिलायें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन कर अपने परिवार का आथिर्क रूप से सहायता कर रहीं हैं और निर्णय प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं हैं। अब ग्रामीण महिलायें रोजगार, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक हुई हैं। अन्ततः यह कहा जा सकता है कि 'जीविका' ने समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन कर महिला सशक्तिकरण को और सुदृढ़ किया है।

विभिन्न चुनौतियों के बावजूद 'जीविका' ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समावेशन में तथा आत्मविश्वास बढ़ाने मील का पत्थर साबित हुआ है। यदि महिलाओं की शिक्षा, कौशल तथा डिजिटल (तकनीकी) प्रशिक्षण, पारदर्शी कार्यप्रणाली, को और अधिक सशक्त किया जाए, तो इन चुनौतियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

संदर्भ सूची:

1. Amrit, R. (2020). Bihar's poorest women are changing their lives: A case study of Bihar Rural Livelihoods Promotion Society (JEEViKA). Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education, 17(1).
2. सिहं, इवानिंदर पाल. (2025). जीविका दीदी: बिहार की ग्रामीण सशक्तिकरण की मूक क्रांतिकारी. The Tribune. Retrieved from- https://www.tribuneindia.com/news/exam-mentor/jeevika-didis-bihars-silent-revolutionaries-of-rural-

empowerment/

3. कुमार, कमलेश. (2026). ग्रामीण Bihar की महिलाओं की वित्तीय आत्मनिर्भरता में जीविका स्वयं सहायता समूहों की भूमिका : एक समीक्षात्मक अध्ययन. International Journal of Humanities And Social Science Research.
4. कुमार, सुरज., और सिहं, विवेक प्रकाश. (2025). महिला नेतृत्व में ग्रामीण विकास: बिहार की जीविका योजना का एक अध्ययन. बिहार जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. 22(1).
5. भारती, निशा. (2025). जीविका (JEEViKA) आजीविका मॉडल केतहत ग्रामीण महिलाओं के वलए चुनौतियां और अवसर. International Journal of Humanities and Social Science Invention. 14(1).
6. Kumar,Sidhant. (2023). Women's Groups and Political Participation: The Role of Jeevika in Local Governance Participation. Impact and Policy Research Review. 2(1).